## विवरण-II

**योजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए किए गये उपायों की सूची**

(i) योजना की मानिटरिंग के लिए 1.4.92 से प्रबन्ध सूचना प्रणाली शुरू की गयी है।

(ii) शहरी लघु उद्यम स्कीम के लिए बैंकों की मार्फत आसानी से संस्थागत वित्त पाने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति गठित की गयी।

(iii) नेहरू रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों का पता लगने के लिए बैंकों के सहयोग से नगर स्तर पर कार्य दल बनाये गये है।

(iv) योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सचिव स्तर पर बैठकें की जाती हैं।

(v) स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का 19 और 20 दिसम्बर, 1995 को एक दो दिवसीय अखिल, भारतीय शहरी गरीबी उपशमन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय प्रशासन मंत्रियों और सचिवों ने भाग लिया था।

(vi) राज्यों के आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय प्रशासन मंत्रियों और सचिवों का 15 जनवरी, 1996 को एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(vii) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और मोनिटरिंग के लिए राज्यों/संघ प्रदेशों से राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) तथा जिला शहरी विकास एजेंसी (डूडा) गठित करने का आग्रह किया गया है।

(viii) आवास तथा आश्रय सुधार योजना को एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया गया जिसका तात्पर्य यह है कि इस योजना की अब 20 हजार तक की आबादी वाले शहरों में लागू किया जा सकता है।

(ix) एक नियत अन्तराल पर प्रत्येक राज्य/संघ प्रदेश को विशिष्ट शासकीय पत्र लिखे जाते है जिनमें वित्तीय व भौतिक प्रगति तथा अन्य ब्यौरों की स्थिति का उल्लेख होता है।

(x) वर्ष 1992-93 से घटिया कार्य निष्पादन वाले राज्यों के लिये नियत धनराशि बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को दी जाने लगी है।

### सैक्टर-4, डी० आई० जेड, क्षेत्र में छज्जों (बाल्कनियों) का निर्माण

711. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सैक्टर-4, डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के ब्लाक नंबर 1 से 8 में सरकारी मकानों में छज्जों (बालकनियों) के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक छज्जों (बालकनियों) का निर्माण न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु):** (क) जी हां। डी० आई० जेड० एरिया, सैक्टर-4, के ब्लाक नं० 1 से 8 तक के सरकारी क्वार्टरों में बाल्कनियों के निर्माण के लिए अगस्त, 1996 में 16.34 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है।

(ख) नई दिल्ली नगर निगम द्वारा वास्तुकीय ड्राइंग्स अब तक जारी तथा पुनः वैधीकृत नहीं किए गए है। नई दिल्ली नगर परिषद् से नक्शे अनुमोदित कराने के प्रयास किए जा रहे है।

(ग) नक्शों पर अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य निधियों की उपलब्धता के आधार पर 6 महीने में पूरा किया जा सकता है।

### Misuse of HUDCO amount by Mineral Area Development Authority

712. **SHRI SANJAY NIRUPAM:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) has allotted a huge amount to Mineral Area Development Authority,

Dhanbad (Bihar) and that money has been misused;

(b) whether any enquiry to probe into the allegations has been instituted; and

(c) if so, the details thereof and if not, what action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT & MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) HUDCO has sanctioned five projects to the Mineral Area Development Authority, Dhanbad with loan commitment of Rs. 278.04 lakhs and Govt. of India subsidy of Rs. 50.44 lakhs details of which are given in the Annexure [*See* Appendix 180, Annexure No. 15]. HUDCO has reported that funds released to the agency have been properly utilised.

(b) and (c) In view of reply to (a) above, questions do not arise.

**Checking the increase of Slums in Delhi**

713. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total number of slum colonies in Delhi and whether their number is swelling day by day;

(b) what steps have been taken/are proposed to be taken to check the further coming up of slum colonies in Delhi; and

(c) whether there is any policy to check the increase in the slums and if so, to what extent it has been successful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT & MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The Government of NCT of Delhi has reported that according to a survey conducted in January, 1990 there were 929 Jhuggi Jhonpari Clusters in Delhi comprising 2.60 lakh jhuggies and having a population of about 13 lakhs. Another survey was conducted in March, 1994 which revealed that the estimated number of Jhuggi Clusters was around 1080, comprising 4.80 lakh jhuggies and having a population of more than 20 lakhs.

(b) and (c) Instructions have been issued by the Government to the land owning agencies/local bodies from time to time to protect public land from encroachment at the initial stage itself through effective measures including fencing, putting up walls, launching criminal transpass cases against the encroachers and taking action against the delinquent staff charged with the responsibility of watch and ward. The Lt. Governor of Delhi has also established a Special Task Force in each of the nine districts of Delhi to collect information, initiate action and activate the land owning agencies to protect and recover the encroached public land.

**गुजरात में पेय जल की अत्यधिक कमी**

714. श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, तथा जामनगर के नगर-निगमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल की अत्यधिक कमी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शहरों में जलापूर्ति हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) क्या सरकार इन शहरों में जलापूर्ति हेतु विदेशी सहायता प्रदान करने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) से (ग) जल आपूर्ति एक राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेय जल आपूर्ति